



न्याय साक्षी

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 Email :- nyaysakshi@gmail.com रायगढ़, शनिवार 02 फरवरी 2019 पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए वर्ष-01, अंक-124

महत्वपूर्ण एवं खास

अमन सिंह का बंगला नहीं हुआ खाली, युकां ने किया प्रदर्शन

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह का बंगला खाली कराने के लिए युवा कांग्रेस के नेताओं ने आज देवेन्द्र नगर स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया।

ट्रैक पर आग लगाकर दौड़ा रहे ट्रेन

शिकागो (आरएनएस)। बर्फीले मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए आपने इंसानों को अंगीठी पर हाथ सेकते तो देखा होगा, मगर अमेरिका के शिकागो में रेल ट्रैक पर जमी बर्फ हटाने और इन्हें ट्रैक से बचाने के लिए उन पर ही आग लगा दी गई।

लोन से अधिक का पैसा जव्त फिर भी भगोड़ा कहते हैं

विजय माल्या का तंज लंदन (आरएनएस)। देश से बाहर इन दिनों लंदन में रह रहे उद्योगपति विजय माल्या ने दिवंगत अपने लिए इंसाफ की मांग की। भगोड़ा बताए जाने को अन्याय करार देते हुए उन्होंने कहा कि डीआरटी रिकवरी ऑफिसर देश में उनकी संपत्ति जव्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना न्याय के ही उन्हें अपराधी करार दे दिया गया है।

अमेरिकी हवाई हमलों में 24 आतंकवादी ढेर

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में हवाई हमले किए जिसमें अल-शबाब के 24 आतंकवादी मारे गए। अमेरिका अफ्रीका कमान ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि मध्य सोमालिया के हिरान क्षेत्र में 'आतंकवादियों के ठिकाने' के समीप एक दिन पहले हमला किया गया।

सीरिया में मारी गई पत्रकार मैरी कोल्विन के परिवार को 2144 करोड़ देने का आदेश

वाशिंगटन (आरएनएस)। वाशिंगटन के एक न्यायाधीश ने द संडे टाइम्स की लंबे समय तक विदेशी संवाददाता रही पत्रकार मैरी कोल्विन की 2012 में हुई मौत को लेकर सीरियाई सरकार से उनके परिवार को 30.2 करोड़ डॉलर देने के लिए कहा है।

रेल बजट 2019 : वंदे भारत एक्सप्रेस से वर्ल्ड क्लास दी जाएगी सुविधा

रेलवे को मिले 64,587 करोड़ नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 पेश करते हुए संसद में ऐलान किया कि इस साल रेलवे बजट 64 हजार 587 करोड़ रुपये का होगा। उन्होंने ऐलान किया कि रेलवे पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेंगे।

पांच लाख की सालाना आमदनी पर कोई नहीं लगेगा टैक्स

मोदी सरकार का ऐतिहासिक ऐलान नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले पांच साल के कार्यकाल का अंतिम बजट आज संसद में पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 पेश करते हुए 5 लाख की तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की बड़ी घोषणा की है, वहीं निवेश के साथ 6.5 लाख तक की आमदनी भी टैक्स फ्री कर दी गई है। जिससे नौकरपेशा लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की इस बड़ी घोषणा से पूरे सामान्य वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं मोदी सरकार ने 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये तीन किशतों में दिए जाने की घोषणा भी की है। मोदी सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का नाम दिया है। जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

विजली से जल्द रोशन होंगे देश के ढाई करोड़ घर

मोदी सरकार ने दिया तोहफा नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि माच तक उन सभी 2.5 करोड़ घरों या परिवारों तक बिजली पहुंच जाएगी, जो अभी इससे वंचित है।

संपत्ति पर कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी संपत्ति पर अस्थायी कब्जे करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। साथ ही टाइलधारि भूस्वामी ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर सकता है, चाहे उसे कब्जा किए 12 साल से अधिक का समय हो गया हो।



श्रीष कोर्ट ने कहा कि ऐसे कब्जेदार को हटाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट कार्यवाही की जरूरत तभी पड़ती है जब बिना टाइल वाले कब्जेधारी के पास संपत्ति पर प्रभावीध सेटल्ड कब्जा हो जो उसे इस कब्जे की इस तरह से सुरक्षा करने का अधिकार देता है

जैसे कि वह सचमुच मालिक हो। जस्टिस एनवी रमणा और एमएम शांतनागौडर की पीठ ने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति जब कब्जे की बात करता है तो उसे संपत्ति पर कब्जा टाइल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि उसका संपत्ति पर प्रभावी कब्जा है। लेकिन अस्थायी कब्जा (कभी छोड़ देना कभी कब्जा कर लेना या दूर से अपने कब्जे में रखना) ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा प्रभावी कब्जे का मतलब है कि ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से हो और इस कब्जे पर वास्तविक मालिक चुप्पी साधे बैठा हो। लेकिन अस्थायी कब्जा अधिकृत मालिक को कब्जा लेने से बाधित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि संपत्ति पर कभी कभार कब्जा कर लेना या उसमें घुस जाना, जो स्थायी कब्जे में परिपक्व नहीं हुआ है, उसे वास्तविक मालिक द्वारा हटाया जा सकता है और यहाँ तक कि वह आवश्यक बल का भी प्रयोग कर सकता है। कोर्ट ने कब्जेदार का यह तर्क भी ठुकरा दिया कि लिमिटेडेशन एक्ट, 1963 की धारा 64 के तहत मालिक ने कब्जे के खिलाफ 12 वर्ष के अंदर मुकदमा दायर नहीं किया।

आयकर विभाग ने राबड़ी व बेटी हेमा की तीन प्रॉपर्टी जव्त करने के लिए आदेश

लालू परिवार को झटका

पटना (आरएनएस)। जव्त किए जाने वाले आयकर विभाग ने बेनामी भूखंडों में पटना के सगुना संपत्ति के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा यादव के तीन भूखंडों को हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी के नाम पर धनौत क्षेत्र में दो भूखंड हैं। ये भूखंड पहले हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी के नाम पर थे, जो बाद में दान में दे दिए गए थे।



14 अरब के स्मारक घोटाले में मायावती पर शिकंजा

लखनऊ (आरएनएस)। अखिलेश यादव पर अवैध खनन और रिवर फ्रंट घोटाले पर शिकंजा कसने के बाद अब ईडी ने मायावती को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में मायावती सरकार के कार्यकाल में कथित 14 अरब के स्मारक घोटाले में ईडी ने बीएसपी चीफ के करीबियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और एनसीआर के 6 ठिकानों पर ताबडोड़ छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने लखनऊ के गोमती नगर में इजिनियरों, टेकेदारों और स्मारक घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे।

कई करीबियों के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी



सतर्कता अधिष्ठान ने 1400 करोड़ (14 अरब) के स्मारक घोटाले की जांच की थी। जांच के लिए विजिलेंस में सात इंसपेक्टर की एक एसआईटी का भी गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। आम चुनाव से पहले कसा शिकंजा स्मारक घोटाले को लेकर मायावती पर शिकंजा कसने का संदेह पहले ही जताया गया था। पहले ही सूचना आई थी कि चुनाव से पहले बीएसपी के दो पूर्व मंत्रियों और मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए मायावती पर शिकंजा कसा जा सकता है। पिछली सरकार में हुई थी जांच हालांकि जिस समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने हाथ मिलाया है।

मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहती आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सबरीमाला मंदिर में प्रतिबंधित उम्र वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया लेकिन इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं एवं सम्मान आहत हुआ, इसका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं

मिड-डे मील में मिला सांप, जांच के आदेश

नांदेड़ (आरएनएस)। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुवार को छात्रों को मिड-डे मील के तहत परोसी गई खिचड़ी में सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। घटना बुधवार को गरगवान जिला परिषद के एक प्राइमरी स्कूल में हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में गुरुवार दोपहर छात्रों को मिड-डे मील का वितरण किया जाना था। इसी दौरान बच्चों को भोजन परोसने से पहले ही खिचड़ी में सांप मिलने की बाद सामने आई, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद यह मामला शीष अधिकारियों तक पहुंचा जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल खिचड़ी को जव्त कर इस मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं मिड-डे मील का खाना ना मिलने के कारण स्कूल के करीब 80 बच्चों को भूखा ही रहना पड़ा।



नयी दिल्ली (आरएनएस)। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ छह फरवरी को सुनवाई करेगी। शीष अदालत की वेबसाइट पर मजबूत नहीं होता। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समूह ने केवल 15 हजार करोड़ रुपये जमा किये हैं। पीठ में न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. के. कौल भी हैं। पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों को पिछले आदेशों का पालन करने के लिए और समय देने से मना कर दिया। पीठ ने कहा कि उसने मामले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है ताकि कानून अपना काम करे। पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों से अगली सुनवाई की तारीख पर निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया।

जींद उपचुनाव में बीजेपी 12 हजार वोटों से जीती कांग्रेस के सुरजवाला तीसरे नंबर पर

जींद (आरएनएस)। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया है। यहां हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिश्रा ने कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज कर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे।

सुप्रीम कोर्ट का सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को निर्देश दिया कि वह सेबी-सहारा मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपये जमा नहीं करने के



वोट मिले। नतीजों में कांग्रेस के रणदीप सुरजवाला को मुंह की खानी पड़ी और वह 22740 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के दिग्विजय चौटाला ने कमबैक किया है। उन्होंने 37631 वोटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं आईएनएलडी को केवल 3454 मत ही हासिल हुए।

लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 4,78,670 अन्य किरायायती मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की कल हुई 42वीं बैठक के दौरान यह मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है।

बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और नवगठित जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के लिए नाक का सवाल बन चुके जींद विधानसभा उपचुनाव में विजयी प्रत्याशी बीजेपी के कृष्ण मिश्रा ने 12 हजार 235 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 50 हजार 566

पीएवाई (शहरी) के अंतर्गत सीएसएमसी की 42वीं बैठक में 4,78,670 मकानों को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश को 1,05,956, पश्चिम बंगाल को 1,02,895, उत्तर प्रदेश को 91,689, तमिलनाडु को 68,110, मध्यप्रदेश को 35,377, केरल को 25,059, महाराष्ट्र को 17,817, ओडिशा को 12,290, बिहार को 10,269 और उत्तराखंड को 9,208 मकान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के

प्रधानमंत्री का 8 को रायगढ़ दौरा टलने की संभावना

सीएम भूपेश बघेल ने कहा-दौरे की तारीख में बदलाव करने पीएम को लिखेंगे पत्र रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 फरवरी को रायगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इसी दिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र के चलते मुख्यमंत्री विधानसभा में व्यस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे छह दौरे की तारीख में आंशिक फेरबदल करने का अनुरोध करने की बात कही है। छह में 8 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सत्र के पहले दिन ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करेंगे, वहीं सत्र के चलते बघेल मंत्रिमंडल सहित प्रदेशभर के विधायक विधानसभा में व्यस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 फरवरी को रायगढ़ दौरे की तारीख पर आंशिक परिवर्तन की संभावना है।

भाजपा शासित राज्यों में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं: शाह

नयी दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों की धार्मिक पृष्ठभूमि देखे बिना उनके कल्याण के लिए काम किये हैं और उन राज्यों में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है चाहे वे किसी धर्म के हों।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान 147 बार केन्द्रीय कक्ष तालियों से गुंजा

नयी दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हिन्दी में अभिभाषण दिया। इस दौरान केन्द्रीय कक्ष 147 बार सदस्यों की मेज की थपथपाहट एवं तालियों से गुंजा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले एवं अंतिम पैसे का अंग्रेजी अंश पढ़ा। बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण में जब रक्षा तैयारियों के संदर्भ में राफेल विमान खरीद सौदे का जिक्र आया तब करीब 40 सेकेंड तक तालियां बजी। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक..वन पेंशन, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक संबंधी उल्लेख पर भी सदस्यों ने तालियां बजायीं। नोटबंदी, जीएसटी, मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों को रिण देने, किसानों

का उल्लेख, गंगा की स्वच्छता, भारत रत्न संबंधी उल्लेख तथा उज्ज्वला योजना का जिक्र होने के समय भी सदस्यों ने तालियां बजायीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के दौरान 142 बार तालियां बजी, वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अभिभाषण का कुछ अंश अंग्रेजी में पढ़े जाने के दौरान पांच बार तालियां बजी। केन्द्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा एवं डॉ. मनमोहन सिंह, भाजपा के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रथम पंक्ति में विराजमान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गुलाम नबी आजाद बैठे थे। वहीं अभिभाषण के दौरान कक्ष में केन्द्रीय मंत्री सुयमा स्वराज, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी भी मौजूद थे।



हिंदू धर्म के खिलाफ चल रही है साजिश:भागवत

धर्म संसद में बोले आरएसएस चीफ

प्रयागराज (आरएनएस)। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सबरीमाला मंदिर में प्रतिबंधित उम्र वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया लेकिन इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं एवं सम्मान आहत हुआ, इसका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं



अपलोड नोटिस के अनुसार

मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहती हैं लेकिन श्रीलंका से लाकर उनको पिछले दरवाजे से प्रवेश कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है। भागवत ने कहा, कोर्ट ने कहा महिला अगर प्रवेश चाहती है तो करने देना चाहिए। अगर किसी को रोका जाता है तो उसको सुरक्षा देकर जहां से अब दर्शन करते हैं वहां से ले जाना चाहिए।

सबरीमाला मामले में संवैधानिक बेंच 6 फरवरी को करेगी सुनवाई

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ छह फरवरी को सुनवाई करेगी। शीष अदालत की वेबसाइट पर मजबूत नहीं होता। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समूह ने केवल 15 हजार करोड़ रुपये जमा किये हैं। पीठ में न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. के. कौल भी हैं। पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों को पिछले आदेशों का पालन करने के लिए और समय देने से मना कर दिया। पीठ ने कहा कि उसने मामले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है ताकि कानून अपना काम करे। पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों से अगली सुनवाई की तारीख पर निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया।



प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं।